निवेश को प्रोत्साहन

रोहित कंसल
दीपंकर सेनगुप्त

जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति – 2021-30 इस केंद्र-शासित क्षेत्र में निवेश तथा औद्योगिक वृद्धि की अग्रणी नीति है। नई औद्योगिक विकास योजना अपनी तरह की सबसे आकर्षक योजना तो है ही, बल्कि इसमें पिछली योजनाओं की कमियाँ भी दूर की गई हैं। इसमें दूर-दराज के इलाकों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान है जिससे संतुलित विकास को बल मिलेगा और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इस नीति में निवेश, वृद्धि और रोज़गार – इन सभी पक्षों पर विवेकपूर्ण तरीके से ध्यान दिया गया हैं। रोज़गार पैदा करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में ऐसे उद्योगों पर ज़ोर दिया गया है जिनमें ज्यादा श्रमिक काम कर सकें और तैयार होने वाला उत्पाद ज्यादा मूल्य और गुणवत्ता का हो।

केंद्र सरकार ने तीन साल पहले विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत 'संविधान के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों सहित सभी प्रावधान' जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू कर दिए। साथ ही, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्न दो केंद्र-शासित क्षेत्रों में पुनर्गठित कर दिया- लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर। दीर्घकालीन नीति इस क्षेत्र और इसकी अर्थव्यवस्था में आमूल बदलाव लाने की थी। इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं तथा क्षमताएँ हैं लेकिन उनके अपेक्षाकृत कम परिणाम निकले हैं।

क्षेत्र के उक्त पुनर्गठन से तुरंत पहले इसकी स्थिति काफी खराब थी। 2018-19 में जम्मू और कश्मीर सरकार का व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 57 प्रतिशत था जिसके लिए अधिकतर धन केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। सरकार पर निर्भरता बहुत अधिक थी और निजी क्षेत्र कमजोर था। (लगभग समान विशेषताओं वाले हिमाचल प्रदेश में सरकारी व्यय मात्र 28 प्रतिशत था।) उस समय, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की प्राप्तियों का 40 प्रतिशत केंद्र सरकार से मिलता था। बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों (करीब 5 लाख) के होने से राज्य की कुल प्राप्तियों का एक चौथाई वेतन और पेंशन में चला जाता था। जम्मू और कश्मीर का प्रति व्यक्ति नेट घरेलू उत्पाद करीब 94,000 रुपये था जो हिमाचल प्रदेश के 1,76,000 रुपये की तुलना में करीब आधा था। जम्मू और कश्मीर में सड़कों का घनत्व हिमाचल प्रदेश की तुलना में पाँचवाँ हिस्सा था और हिमाचल प्रदेश के विपरीत, जम्मू और कश्मीर अपनी विशाल जल-विद्युत क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पा रहा था।

यह टिकाऊ स्थिति नहीं था और इसे बदलना ज़रूरी था। जम्मू और कश्मीर को ऐसी स्थिति में लाना ज़रूरी था ताकि निजी उद्यम और निवेश यहाँ आएं और ज्यादा नौकरियाँ तथा आय सृजित होने से अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ऐसे बदलाव के लिए उपयुक्त आर्थिक रणनीति ज़रूरी थी।

रोहित कंसल जम्मू और कश्मीर में कार्यरत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। ईमेल: rohitkansal1@gmail.com
दीपंकर सेनगुप्त जम्मू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ईमेल: dsen68@gmail.com

आर्थिक नीतियों का निर्माण

किसी क्षेत्र के लिए उचित आर्थिक नीति के निर्माण के लिए उस क्षेत्र की सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों का जायजा लेना ज़रूरी होता है। यह बात जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होती है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ उत्पादित वस्तुओं की परिवहन लागत अधिक होगी जिससे उनकी कीमत भी बढ़ेगी। इसलिए महंगी वस्तुओं के कारोबार के लिए उचित आर्थिक रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें निवेशकों तथा नीति-निर्माताओं को इस तरह निर्देशित किया जाए कि वे ऐसी विशिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा दें जो ऐसे खास ग्राहकों की पसंद की हों जो परिवहन लागत के कारण अधिक कीमत होने पर भी इन वस्तुओं/सेवाओं को खरीदें।

ऐसे अनेक उत्पाद/सेवाएँ हो सकती हैं जिनका क्षेत्र-विशेष में उत्पादन/निर्माण दीर्घ कालावधि में सम्बन्धित कौशल। स्थानीय जानकारी के विकास से संभव हुआ है और उस क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति की वजह से स्वाभाविक रूप से वहाँ वह उत्पादन/निर्माण होता हो। जम्मू और कश्मीर में अनेक उत्पादों/सेवाओं से सम्बन्धित कौशल और स्वाभाविक स्थितियाँ मौजूद हैं और उनपर ध्यान दिए जाने से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव की शुरूआत हो सकती है।

जहां तक स्थानीय उत्पादों का प्रश्न है, इस क्षेत्र के हस्तशिल्पों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। जम्मू और कश्मीर में बड़ी मात्रा में सेब पैदा होता है और यहाँ अखरोट और केसर जैसे उत्पाद भी हैं जो जिनका आकार और वजन कम लेकिन कीमत ज्यादा होती है। पाँच हजार वर्ष से मशहूर यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य, हथकरघे और हस्तशिल्प के अनूठे उत्पाद और अद्‌भुत पकवान जम्मू और कश्मीर को लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना देता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में जल-विद्युत संसाधन और बढ़िया काम करने वाले लोग हैं और कुछ दुर्लभ खनिज भी यहाँ मिलते हैं।

केंद्र-शासित जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के प्रशासन ने केंद्र सरकार की सलाह से ऐसी अनेक नीतियाँ लागू की हैं जो निवेशकों के अनुकूल और उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली हैं। इन नीतियों में क्षेत्र की उक्त स्वाभाविक अनुकूलताओं और रुकावटों का पूरा ध्यान रखा गया है।

निवेश को बढ़ावा

जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति – 2021-30 इस केंद्र-शासित क्षेत्र में निवेश तथा औद्योगिक वृद्धि की अग्रणी नीति है। नई औद्योगिक विकास योजना अपनी तरह की सबसे आकर्षक योजना तो है ही, बल्कि इसमें पिछली योजनाओं की कमियाँ भी दूर की गई हैं। इसमें दूर-दराज के इलाकों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान है जिससे संतुलित विकास को बल मिलेगा और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इस नीति में निवेश, वृद्धि और रोज़गार– इन सभी पक्षों पर विवेकपूर्ण तरीके से ध्यान दिया गया हैं। रोज़गार पैदा करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में ऐसे उद्योगों पर ज़ोर दिया गया है जिनमें ज्यादा श्रमिक काम कर सकें और तैयार होने वाला उत्पाद ज्यादा मूल्य और गुणवत्ता का हो।

इनमें इस केंद्र-शासित क्षेत्र के पारम्परिक रूप से सशक्त उद्योग, जैसे पर्यटन, हस्तशिल्प और बागवानी तो शामिल हैं ही, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इससे जुड़ी सेवाएँ और स्वास्थ्य सेवा आदि शामिल हैं। इस नीति में वर्तमान सशक्त उद्यमों से जुड़े क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है – जैसे बागवानी में फसल तैयार होने के बाद उसके प्रबंधन से जुड़े काम तथा फिल्म पर्यटन जैसे पर्यटन के विविध रूप आदि।

पुराने अनुभवों को देखते हुए, इस नीति में वित्तीय सहायता को लेकर भी पिछली नीतियों की तुलना में ज्यादा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। पिछली नीतियों में राज्य में निवेश लाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी और करों में छूट दी गईं। लेकिन वित्तीय प्रोत्साहनों पर आधारित ऐसे अनेक निवेशों को उन क्षेत्रों से नहीं जोड़ा गया जिनमें जम्मू और कश्मीर स्वाभाविक रूप से सशक्त था। इसलिए वित्तीय मदद समाप्त होते ही ऐसे उद्यम टिक नहीं सके और उन्हें बंद करना पड़ा। नई नीति में उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जिनमें राज्य की स्थिति स्वाभाविक रूप से अच्छी है। सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का 53 प्रतिशत हिस्सा है इसलिए इस नीति में एक स्पष्ट सकारात्मक सेवा क्षेत्र सूची बनाई गई है जिसमें शामिल उद्यमों को प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इनमें पर्यटन, फिल्म पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और कौशल विकास आदि शामिल हैं।

किसी क्षेत्र के लिए उचित आर्थिक नीति के निर्माण के लिए उस क्षेत्र की सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों का जायजा लेना ज़रूरी होता है। यह बात जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होती है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ उत्पादित वस्तुओं की परिवहन लागत अधिक होगी जिससे उनकी कीमत भी बढ़ेगी। इसलिए महंगी वस्तुओं के कारोबार के लिए उचित आर्थिक रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें निवेशकों तथा नीति-निर्माताओं को इस तरह निर्देशित किया जाए कि वे ऐसी विशिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा दें जो ऐसे खास ग्राहकों की पसंद की हों जो परिवहन लागत के कारण अधिक कीमत होने पर भी इन वस्तुओं/सेवाओं को खरीदें।

इस औद्योगिक नीति के प्रारम्भ के बाद की नीतिगत घोषणाओं और बजट प्रावधानों में इसी नीति के मूलभूत पक्षों को ही सशक्त किया गया है। उक्त घोषणाओं और बजट प्रावधानों का उद्देश्य इसी नीति के विविध पक्षों का विस्तार करना और उन्हें सशक्त बनाना है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि उचित नीति तथा सुसंगत बजट प्रावधानों में सही ताल-मेल होने से कई गुना अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसीलिए इस वर्ष के बजट के अनेक प्रावधानों में निवेश आकर्षित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने पर ज़ोर दिया गया है।

पर्यटन

जम्मू और कश्मीर को लंबे समय से पर्यटन के साथ जोड़ा जाता है लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि पर्यटकों की

कुल संख्या अथवा जनसंख्या के अनुपात में पर्यटकों की आमद के मामले में यह तत्कालीन राज्य कभी भी देश के चोटी के दस राज्यों में नहीं रहा। इस केंद्र-शासित क्षेत्र के वर्तमान बजट में 75 नए पर्यटन-केन्द्रों के लिए मदद और संसाधन दिए गए हैं ताकि क्षेत्र की पर्यटन अर्थव्यवस्था का विस्तार हो और बहुत अधिक रोज़गार की संभावना वाले इस क्षेत्र में ज्यादा रकम आए। इससे जुड़े दूसरे विभागों के कार्यों और उनको दिए गए वित्तीय प्रावधानों के साथ समझदारी से ताल-मेल बिठाया जा रहा है, जैसे संस्कृति विभाग परम्परागत मेलों और सूफी समारोहों को नए सिरे से प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें से अनेक दूर-दराज के अनजान इलाकों में हैं जो जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण पर्यटन नेटवर्क का हिस्सा हैं। इनसे स्थानीय युवाओं को प्रोत्साहन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन प्रयासों के साथ तालमेल से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। आंकड़ों को देखने से लगता है कि इन प्रयासों का लाभ मिल रहा है। पिछले वर्ष नवंबर में जम्मू और कश्मीर में पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक आए। 27 मार्च को 36,473 पर्यटक ट्यूलिप गार्डन देखने आए। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस वर्ष 4 अप्रैल श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इतिहास में व्यस्ततम दिन रहा। उस दिन 90 उड़ानों में 15,014 लोग या तो श्रीनगर आए या यहाँ से गए।

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने एक और पहल की है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच पिछले दिनों व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) हुआ है। इसमें कारोबार के लिए बाज़ार, निवेश और पर्यटन का विस्तार करने के प्रावधान हैं।

बागवानी

बागवानी के लिए बजट में उत्पादकता और आमदनी – दोनों बातों पर ध्यान दिया गया है। बजट में प्रोत्साहित किए गए क्षेत्रों में शामिल हैं -कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को बढ़ावा देना,ज्यादा बगीचे लगाकर सेब की उत्पादकता बढ़ाना, कम जगह में आ जाने वाले और ज्यादा दाम देने वाले कृषि-उत्पादों, जैसे सुगंध वाली और नकदी फसलों तथा सब्जियों को प्रोत्साहित करना आदि। केसर और अन्य उत्पादों के लिए जीआई प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इन प्रयासों से इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादकता बढ़ सकेगी तो इस क्षेत्र का विस्तार चार गुना हो जाएगा। फलों से विभिन्न उत्पाद तैयार कर इसके मूल्य-संवर्धन से (जो इस समय बहुत कम है) बागवानी में काफी वृद्धि हो सकेगी और बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकेगा।

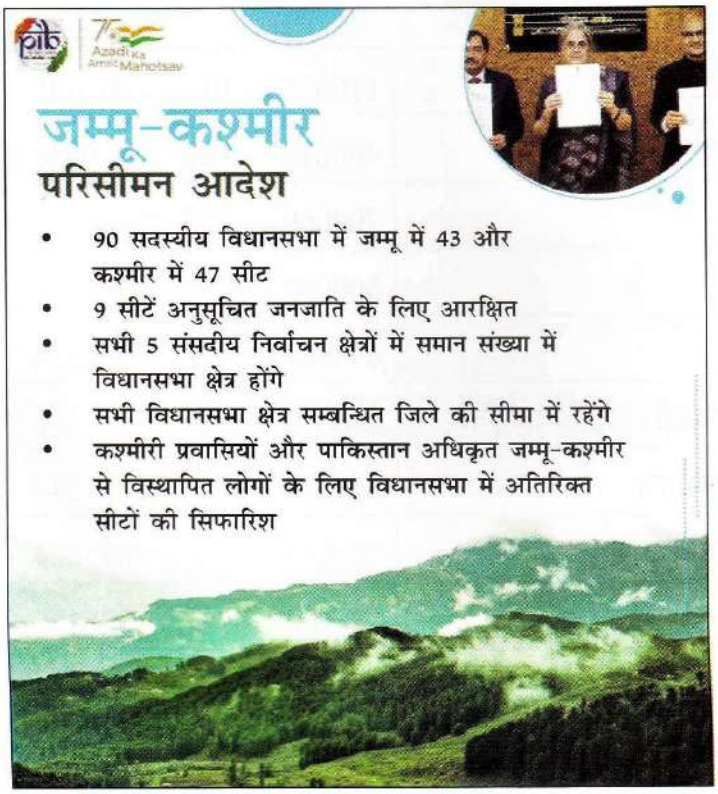

विदेश व्यापार और निवेश

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने एक और पहल की है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच पिछले दिनों व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) हुआ है। इसमें कारोबार के लिए बाज़ार, निवेश और पर्यटन का विस्तार करने के प्रावधान हैं। जम्मू और कश्मीर को इस समझौते से लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूएई कश्मीर से घनिष्ठता के साथ सुपरिचित है। अत: इन संपर्कों और संभावनाओं का लाभ उठाते हुए, खाड़ी क्षेत्र से निवेश प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में निवेश बढ़ाना

इन नीतियों का जम्मू और कश्मीर में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्षेत्र में संवैधानिक अनिश्चितता समाप्त होने, कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, मूलभूत सुविधाओं पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने तथा आर्थिक विकास पर केन्द्रित कार्य-नीति अपनाए जाने से निवेशकों की इस क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ी है और अनेक नीतियों के प्रति उनका रुख उत्साहजनक रहा है।

जो निवेशक पहले तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में निवेश करने से कतराते थे, वे अब नवगठित केंद्र-शासित क्षेत्र में निवेश करने के लिए उत्साहित नज़र आ रहे हैं। यहाँ के प्रशासन को 51,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं जिनसे 2.37 लाख लोगों को रोज़गार मिलने का अनुमान है। केंद्र-शासित क्षेत्र की औद्योगिक नीति में 10 साल में 28,400 करोड़ रुपये किए जाने का प्रावधान है। इसे देखते हुए निवेश की उक्त संभावनाएं, हर तरह से प्रभावशाली लगती हैं। साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि अब इस क्षेत्र में विदेशी, खास तौर से यूएई के सुपरिचित नामों और ब्रांडों की दिलचस्पी बढ़ी है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जिन क्षेत्रों में निवेश की पेशकश हुई है और प्रस्ताव मिले हैं उनमें से अधिकतर सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सकारात्मक क्षेत्रों की सूची में शामिल हैं। ये तथ्य इस क्षेत्र और निवेशकों – दोनों के लिए उत्साहवर्धक हैं।

लाभदायक क्षेत्रों में निवेश की रणनीति

जम्मू और कश्मीर में धन लगाने से पहले निजी निवेशक क्या अपेक्षा रखता है? इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि उसे उसके निवेश पर लाभ मिले। इसके किए ज़रूरी है कि निवेशक की व्यावसायिक योजना राज्य की प्राकृतिक, पारम्परिक और मानव संसाधनों से कितनी घनिष्ठता से जुड़ी है। एक सुव्यवस्थित कारोबार ऐसे ही पुख्ता आधार पर लाभदायक बना रहता है, हमेशा सरकारी सब्सिडी

के भरोसे नहीं टिका रहता। जम्मू और कश्मीर में पिछले दिनों पर्यटकों की भीड़ ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पता चलता है कि यह क्षेत्र निवेशकों के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। इसलिए, इस क्षेत्र में, खास कर अब तक अनजाने रहे इलाकों में, निवेश करना काफी लाभदायक हो सकता है। बागवानी और फसल के बाद उत्पांद के मूल्य-संवर्धन की प्रक्रियाओं में निवेश भी फायदेमंद हो सकता है। इन दोनों क्षेत्रों में यह केंद्र-शासित क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, साथ ही इन उद्यमों के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी भी है और ये पारम्परिक क्षेत्र भी हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में निवेश पर अच्छा मुनाफा हो सकता है।

निवेशक मुनाफे की अच्छे संभावनाओं वाले अनेक अन्य क्षेत्रों में भी निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूचना टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी सेवाओं में बड़ी संख्या में कुशल स्थानीय युवाओं को काम पर लिया जा सकता है। सूचना टेक्नोलॉजी की प्रगति तथा कोविड-19 की वजह से, इस क्षेत्र में घर से ही काम करने का रुझान बढ़ गया है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश में मुनाफे की अच्छी संभावनाएं हो गई हैं।

निवेशक मुनाफे की अच्छे संभावनाओं वाले अनेक अन्य क्षेत्रों में भी निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूचना टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी सेवाओं में बड़ी संख्या में कुशल स्थानीय युवाओं को काम पर लिया जा सकता है। सूचना टेक्नोलॉजी की प्रगति तथा कोविड-19 की वजह से, इस क्षेत्र में घर से ही काम करने का रुझान बढ़ गया है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश में मुनाफे की अच्छी संभावनाएं हो गई हैं।

जम्मू और कश्मीर में ऐसे ही नवीन संभावनाओं वाले क्षेत्रों में सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य और समग्र आरोग्य से जुड़े उद्यम शामिल हैं।

लेकिन मात्र सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए जम्मू और कश्मीर में निवेश करना अविवेकपूर्ण होगा और इससे लंबे समय में नुकसान ही होगा। इस केंद्र-शासित क्षेत्र की नई आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए निवेशकों के लिए यही फायदेमंद होगा कि वे यहाँ निवेश करते समय यहाँ के लोगों और परिस्थितियों से जुड़ा रहे।

उज्ज्वल भविष्य की ओर

सरकार की आर्थिक नीति का उद्देश्य ऐसा बदलाव लाना है जिसमें नया जम्मू और कश्मीर निरंतर प्रगतिशील भारत के साथ-साथ चले और जहां घूमने तथा संभावनाएं तलाशने के नए-नए इलाके हों। यहाँ का बागवानी क्षेत्र ऐसे फल उपजाए और फलों से बनने वाले उत्पाद तैयार करे जो गुणवत्ता में विश्व-स्तर के हों। सदियों के अनुभव और संस्कृति के बीच विकसित यहाँ के हस्तशिल्पों का दुनिया भर में नई ऊर्जा से निर्यात किया जाए। इस क्षेत्र को भारत की एक-तिहाई जल-विद्युत पैदा करनी होगी। इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित सेवाओं, औषधि उद्योग, वस्त्र उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास की भी बहुत संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य, आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र देश भर में बेजोड़ हो सकता है।

सरकार की नीति इन सभी संभावनाओं को सफल बनाने की है। निजी निवेशक अगर सरकार के साथ ताल-मेल से अपनी निवेश-नीतियाँ बनाएंगे तो इस केंद्र-शासित क्षेत्र में निवेश करने से उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। ■

(इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के पूर्णत: निजी विचार हैं।)

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंज़िल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237